

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06122023-250449  
SG-DL-E-06122023-250449असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 353]	दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 6, 2023/अग्रहायण 15, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 319
No. 353]	DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 6, 2023/AGRAHAYANA 15, 1945	[N. C. T. D. No. 319

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIभूमि एवं भवन विभाग  
(भूमि अधिग्रहण शाखा)  
अधिसूचना

दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2023

फा. सं. 9(34)/भूमि एवं भवन/भू.अधि./2023/7846.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 की अधिसूचना सं० एस०ओ० 2740 (ई), दिनांक 21 जुलाई, 2015 की अधिसूचना सं. एस.ओ. 2004 (ई) के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापन (सामाजिक प्रभाव, आंकलन, अनुज्ञा) में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार नियमावली, 2014 के नियम 4 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 को, जिसे दिनांक 13 जून, 2017 की अधिसूचना सं० फा. 8(2)/9/2015/भूमि एवं भवन/भू०अधि०/2373 द्वारा चिन्हित किया गया था, भूमि अधिग्रहण हेतु सामाजिक प्रभाव आंकलन अध्ययन तथा सामाजिक प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निर्दिष्ट करते हैं, जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण, दक्षिण

राजस्व जिले के मैदानगढ़ी राजस्व एस्टेट में सार्क विश्वविद्यालय से सीएपीएफआईएमएस तक सड़क के निर्माण हेतु जन प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण करने का प्रयोजन रखती है।

यह भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली-110002 भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर सामाजिक प्रभाव आंकलन का अध्ययन करेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अशोक कुमार यादव, उप-सचिव (भूमि एवं भवन)

## LAND AND BUILDING DEPARTMENT

(Land Acquisition Branch)

### NOTIFICATION

Delhi, the 6th December, 2023

**F. No. 9(34)/L&B/LA/2023/7846.**—In the exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 4 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Social Impact, Assessment and Consent) Rules, 2014, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S.O.2740 (E) dated 21<sup>st</sup> October 2014, read with S.O. 2004 (E) dated 21<sup>st</sup> July 2015, the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to assign the Indian Institute of Public Administration, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi 110002 which was identified as Social Impact Assessment Unit vide Notification No. F 8(2)/9/2015/L&B/LA/2373 dated 13<sup>th</sup> June 2017, to carry out Social Impact Assessment Study and to prepare Social Impact Assessment report for acquisition of land, which the Delhi Development Authority intends to acquire land for public purpose for construction of Road from SAARC University to CAPFIMS at Maidangarhi Revenue Estate of South Revenue District.

The Indian Institute of Public Administration, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi 110002 shall carry out the Social Impact Assessment study as per the provisions of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 within a period of six months from the date of publication of this notification in official gazette.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor  
National Capital Territory of Delhi,

ASHOK KUMAR YADAV, Dy. Secy. (Land & Building)